हरियाणा में तीन चौथाई बहुमत से सरकार बनायेगी कांग्रेस: पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने भाजपा को बता दिया कि घमंड व अहंकार से राज नहीं कर सकते

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट 30 सितम्बर से हरियाणा के चुनाव प्रचार अभियान पर हैं। आज उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। वे 2 और 3 अक्टूबर को भी हरियाणा में ही रहेंगे।

■ कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने हरियाणा में भवानी खेड़ा, फरीदाबाद, घरौंडा, समालखा, नांगल चौधरी, हथीन, बादशाहपुर में चुनाव सभायें कीं। वे दो और तीन को सोहना, जगाधरी, महेन्द्रगढ़, तोशाम, बरवाला, पलवल में चुनावी दौरा करेंगे।

जयपुर, 1 अक्टूबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जनता ने कांग्रेस को विजयी बनाने का मन बना लिया है। जो लोग 300 पार, 400 पार का नारा लगाते थे, जनता ने उनकी नकारात्मक सोच और घमण्ड का जवाब देते हुए लोकसभा चुनावों में उन्हें बहुमत भी पार करने नहीं दिया। देश की जनता ने भाजपा को आईना दिखाते हुए बता दिया कि आप घमण्ड और अहंकार से राज नहीं कर सकते, तानाशाही तरीके से राज नहीं कर सकते, आप लोगों की भावनाओं से खेलकर, मंदिर-मस्जिद की बात करके वोट नहीं ले सकते।

पायलट 30 सितम्बर व 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहे। अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान पायलट ने 30 सितम्बर को हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा एवं फरीदाबाद एन.आई.टी. तथा 1 अक्टूबर को घरौंड़ा, समालखा, नांगल चौधरी, हथीन तथा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को सम्बोधित किया।

पायलट 2 अक्टूबर को हरियाणा के सोहना एवं जगाधरी तथा 3 अक्टूबर को महेन्द्रगढ़, तोशाम, बरवाला, पलवल विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी दौरे पर रहेंगे।

सभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने देश और प्रदेश की भाजपा की सरकार के दस सालों के कुशासन को झेला है। किसानों को परेशान किया गया, उन पर लाठी-गोलियां चलायी गईं, सैकड़ों किसानों ने शहादत दी। भाजपा धर्म, जाति, मंदिर-मस्जिद की बातें करके वोट लेना जानती है। भाजपा का खाद, बिजली, पानी, सड़क, निवेश, विकास जैसे मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि भाजपा के दस सालों के कुशासन, भय, पक्षपात और भाई से भाई को लड़ाने की सोच, दमनकारी राजनीति का पुरजोर जवाब देते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें।

'दूसरे राज्यों से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मौजूद थे, और उन्होंने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि एफ.एस.एल. और डी.एन.ए. रिपोर्ट समय पर तैयार करने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराना राज्य सरकार का दायित्व है।

इस संबंध में वर्ष 2014 से हाईकोर्ट निरंतर आदेश पारित कर रहा है, लेकिन आदेशों की पालना नहीं हो रही है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 से वर्षवार लंबित मामलों का रिकॉर्ड भी पेश किया गया, जिसमें सामने आया कि लंबित मामले छह साल में 3136 से बढक़र 20 हजार से अधिक हो गए हैं।

अदालत ने अधिकारियों को कहा कि गंभीर मामलों में यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय हो सकता है। वहीं, राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण आरोपी को अकारण जेल में रखा जाता है तो उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। प्रकरण 13 साल की बालिका से दुष्कर्म से जुड़ा है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता प्रकट नहीं हुई है। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा कि अदालत यह विकल्प क्यों न आपनाए कि रिपोर्ट में देरी के चलते सरकार पर हर्जाना लगाकर राशि आरोपी को दी जाए।

कई दशकों के इंतज़ार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोग "सिंकिंग फीलिंग" कहते हैं, वैसी स्थिति थी।

जापान की सभी समस्याओं की जड़ वहाँ की जनसंख्या में लगातार कमी आना है। हालाँकि यह स्थिति अकेले जापान की ही नहीं है। विकसित विश्व के अधिकांश देश जनसंख्या के कम होते जाने की समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन जापान में यह समस्या कुछ ज्यादा ही विकट है। जनसंख्या के कम होने से गाँव वीरान हो गये हैं, पढ़ने वाले छोटे बच्चों के अभाव में किन्डरगार्टन स्कूल बंद हो गये हैं तथा फैक्ट्रियों को और कारीगर नहीं मिल रहे हैं।

जापान द्वारा आप्रवासन (बाहर से आकर बस जाना) की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण, जापान की हालत खराब हो गई है। जापान की जनसंख्या में जापान मूल के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अब आकर, जब जनसंख्या कम होते जाने का दबाव बहुत विकट हो गया है, जापान कुछ विदेशियों को यहाँ आकर बसने की अनुमति देने लगा है। कुछ लोग पड़ोसी देश चीन से जापान में पहुँच रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है तथा इनका आना भी किसी भी समय रूक सकता है क्योंकि चीन स्वयं भी जनसंख्या में कमी की समस्या का सामना कर रहा है।

वस्तुत: कोई भी नई सरकार जनसंख्या की प्रवृत्ति (ट्रैन्ड) को उलट तो नहीं सकती। जनसंख्या ट्रैन्ड बहुत लम्बी अवधि के बाद ही बदल पाते हैं। लेकिन नीतियों के बदलने से कुछ राहत जरूर मिलती है। इसके अलावा, जापान की स्थिति इसलिये भी नहीं उलट सकती, क्योंकि वहाँ की करीब 30 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर की है। उनकी पैंशन तथा चिकित्सा सुविधा में समाज की आय का एक अच्छा-खासा हिस्सा काम आ जाता है।

लेकिन और अधिक राहत युक्त आप्रवासन नीति काम करने वाले हाथों की कमी को कम कर सकती है। इसके अलावा, जापान को महिलाओं के प्रति अपनी सोच एवं रवैया बदलना होगा, जो अभी भी जबरदस्त भेदभाव का सामना कर रही हैं। काम में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी से कुछ राहत की स्थिति बन सकती है। लेकिन हाल ही की कुछ सरकारें महिलाओं की प्रजनन-संबंधी भूमिका के राग अलापती रही हैं।

और ज्यादा दबाव बना रहे आर्थिक मुद्दों में शामिल एक मुद्दा है- कीमतों की स्थिरता, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। कीमतें अधिकांशत: तो कम ही हुई है और अगर बढ़ी भी हैं तो वर्ष में करीब 0.3 प्रतिशत मात्र।

इस जबरदस्त सुस्ती एवं मंदी के विरूद्ध, "बैन ऑफ जापान" ने अपना महँगाई लक्ष्य 2 प्रतिशत रखा था। माँग को प्रोत्साहित करके, कीमतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सैन्ट्रल बैन ने अपनी ब्याज दर कम कर दी थी।

पर्यावरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करती है। भाजपा सोनम वांगचुक पर जो बल प्रयोग कर रही है, वह उसे गैंगस्टर्स पर करना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर अहंकारी और अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया और कहा, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण मार्च कर रहे लद्दाखी लोगों को गिरफ्तार किया है।

खड़गे ने कहा कि वांगचुक की मांगों को जनता का समर्थन है। मोदी सरकार अपने करीबी उद्योगपतियों की खातिर लद्दाख के हिमालयी ग्लेशियर्स, जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हैं, का दोहन करना चाहती है।

कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने इस घटना का संबंध महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ा। उन्होंने कहा, गांधी जयंती से पहले भारत सरकार एक बार फिर गांधी के विचारों की हत्या कर रही है। वांगचुक जी की गिरफ्तारी से स्पष्ट होता है कि सरकार हर उस व्यक्ति से डरती है, जो अपने अधिकारों के लिए बोलता है।

उन्होंने भाजपा पर लद्दाख की जनता का मुंह बंद कर यह क्षेत्र अपने कॉरपोरेट मित्रों को देने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी कायरतापूर्ण हरकत गांधी के रास्ते पर चलने वालों को नहीं रोक सकती है।

यह पहली बार नहीं है, जब वांगचुक ने लद्दाख की तरफ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की हैं।

मार्च में उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उद्योगों द्वारा लद्दाख के संवेदनशील लैंड स्केप के दोहन के खिलाफ 21 दिन का उपवास किया था।

200 भारतीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों से सहायक होंगे, उनका भाषा-कौशल साझा करेंगे तथा फ्रांसीसी विद्यार्थियों से जुड़ेंगे। यह अनुभव उन्हें फ्रांसीसी भाषा एवं संस्कृति को समझने तथा वहाँ के लोगों के निकट रहते हुये काम करने का अवसर प्रदान करेगा।

फ्रांस जाने वाले इन शिक्षकों के लिये, आई.बी.आई.एस. होटल एयरोसिटी, नई दिल्ली में एक प्री-डिपार्चर सत्र आयोजित किया गया, जहाँ ग्रैगोआर टुमेल, जो आई.एफ.आई. के निदेशक तथा नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास में को-ऑपरेशन एण्ड कल्चरल अफेयर्स के काउन्सलर हैं, ने विदेश जाने से पहले असिस्टैंट्स से बातचीत की।

"द फ्रैंच इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया" के निदेशक ग्रैगोआर टुमेल ने कहा, "लैंग्वेज़ असिस्टैंट प्रोग्राम हमारे दोनों देशों को नज़दीक लाता है। लैंग्वेज़ असिस्टैंट्स फ्रांस में भारतीय संस्कृति तथा भारत में फ्रांसीसी संस्कृति के विशिष्ट अधिकार प्राप्त राजदूत होते है। फ्रांसीसी युवाओं के साथ फ्रांसीसी शिक्षा व्यवस्था में कार्य करके, वे पारस्परिक सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण में एक रणनैतिक भूमिका निभाते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट द्विपक्षीय फ्रांस-भारत संबंधों की मुख्य चाबी है।

इस वर्ष इस प्रोग्रेस के लिये 206 भारतीय भाषा सहायकों का चयन हुआ है। इनके अलावा इनके साथ, 61 वापस लौटने वाले असिस्टैंट्स होंगे, जिन्होंने फ्रैंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ अपने अनुबंधों का नवीनीकरण करा लिया है। ये असिस्टैंट्स फ्रांस के विभिन्न शैक्षिक विभागों में काम करेंगे, जिन्हें "ऐकेडमीज़" कहा जाता है।

'हमारी अनुमति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस अदालत की अनुमति के बिना कोई भी सम्पत्ति ध्वस्त नहीं की जायेगी तथा इनमें अपराध के आरोपियों की सम्पत्तियाँ भी शामिल हैं। पूर्ववर्ती सुनवाई में, अदालत ने कहा था कि अवैध ध्वस्तीकरण की एक भी घटना संविधान की "प्रकृति" के विरुद्ध है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों का प्रतिनिधित्व किया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के लिये इस केस को सुरक्षित रख लिया है तथा सारे देश में अवैध बुलडोज़र ध्वस्तीकरण पर 17 सितम्बर को लगाये स्टे को आगे बढ़ा दिया है। अदालत ने बुलडोज़र डिमॉलिशन केसों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप, जिनमें यू.एन. स्पेशल रैपॉच्र्योर का हस्तक्षेप भी शामिल है, की अनुमति नहीं दी।

इज़रायली सेना ने बेरुत पर हवाई व जमीनी हमले किये

येरूशलम, 01 अक्टूबर। हिज्बुल्लाह चीफ सैय्यद हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद इज़रायली सेना का अगला अभियान शुरू हो गया है। आज इज़रायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के सैनिक लेबनान में घुस गए हैं। इज़रायली सेना ने गाज़ा में हमास के विनाश के तर्ज पर अब बेरूत में हिजबुल्लाह को भी जड़ से उखाड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर पहले बेरूत समेत लेबनान के कई इलाकों में इजरायली सेना ने जमीनी और हवाई हमले में हिजबुल्लाह आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। इससे पूरे लेबनान में हड़कंप मच गया है।

जमैका के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर। जमैका के प्रधानमंत्री होलनेस भारत यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को होलनेस और उनके देश से आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का भी आदान-प्रदान किया गया।

पीएम मोदी ने कहा कि जमैका भारत का लंबे समय से मित्र रहा है। प्रधानमंत्री होलनेस से कई बार मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ पूरे कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ऊर्जा देगी।

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 180 साल पहले भारत से जमैका गये लोगों ने आपसी संबंधों की मजबूत नींव रखी थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।चार सी (संस्कृति, क्रिकेट, राष्ट्रमंडल और कैरीकॉम कैरेबियन समुदाय) हमारे संबंधों की विशेषता हैं। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा है। भारत हमेशा जमैका की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध विकास भागीदार रहा है।

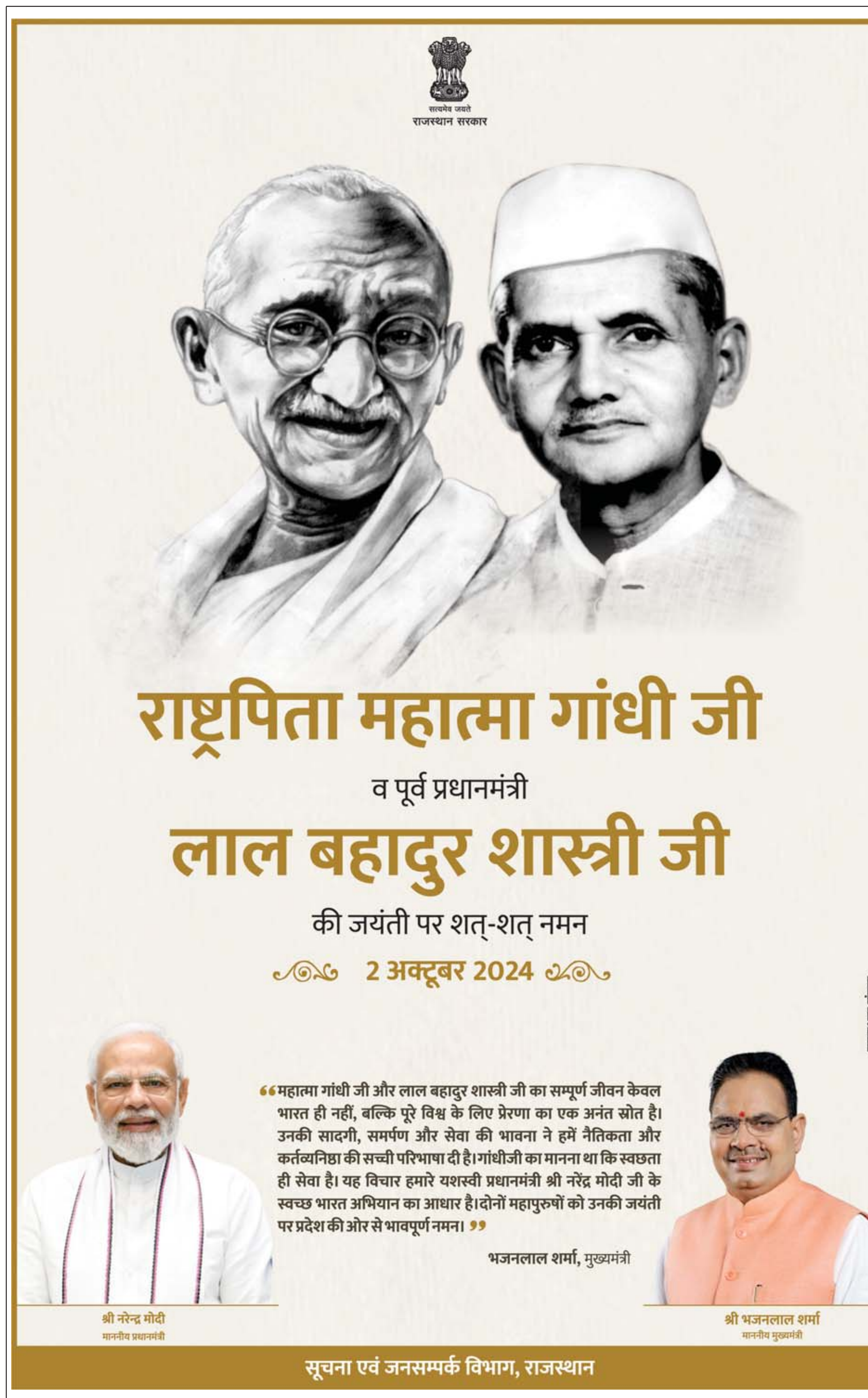

मुख्यमंत्री ने कॉनक्लेव को राज्य के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ हिन्दुस्तान पेट्रोलियन के चेयरमैन, भारत इलैक्ट्रोनिक्स के सी.एम.डी., कॉनकोर के सी.एम.डी. ने राजस्थान सरकार के साथ काम करने के सुखद अनुभव बताये।

क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर), एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरईडीए, पीजीसीआईएल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईटीडीसी), फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई), न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), आईआरसीटीसी, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई), ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), एफआईसीएसआई (खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल), मैनेजमेंट एंड आंत्रप्रिन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स काउंसिल (एमईपीएससी) शामिल हैं।

राजस्थान सरकार को आगामी ग्लोबल इन्वैस्टमेंट समिट के लिए शुभकामना देते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश नारंग ने कहा कि राज्य सरकार ने हमें हर स्तर पर महत्वपूर्ण और त्वरित समर्थन दिया है। रिफाइनरी की न केवल वर्तमान जरूरतों के लिए, बल्कि भविष्य के इसके संभावित विस्तार के लिए भी भूमि का आवंटन सरकार द्वारा शीघ्रता से किया गया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन ने कहा, देश के डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में राजस्थान एक बड़े औद्योगिक राज्य के रूप में उभर रहा है।

कॉनकॉर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय स्वरूप ने एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) जैसे परिवहन के टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल साधनों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में बताया और लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने में राजस्थान सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार क्षमता है, प्रचुर खनिज भंडार हैं और कुशल कार्यबल है।

इनके जरिए हम राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों - दोनों के लिए साझा समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ मिलकर हम सब 'विकसित भारत' और 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, इस कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के राज्य सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा, राज्य में काम कर रहे सी.पी.एस.ई'ज़ का आभार मैं राज्य सरकार की ओर से व्यक्त करता हूं क्योंकि राज्य की समृद्धि और विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 निजी क्षेत्र और सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई.) से निवेश आकर्षित करने पर समान रूप से जोर देता है।

इस अवसर पर एक प्रेजेंटेशन देते हुए उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा कि दिल्ली से नजदीक होने की वजह से राजस्थान एक स्ट्रैटेजिक लोकशन है और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं है जिसका फायदा राज्य में निवेश करके केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज उठा सकती हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908